P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-6* ISSUE-11* July- 2019
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

उत्तर प्रदेश की औद्योगिक प्रगति का विवेचनात्मक अध्ययन

मनू देवी
असिस्टेण्ट प्रोफेसर,
अर्थशास्त्र विभाग,
स्नेहलता मेमोरियल डिग्री कालेज,
रसूलाबाद, कानपुर देहात

सारांश

प्रस्तुत लेख उ0प्र0 के ''औद्योगिक प्रगति का विवेचनात्मक अध्ययन'' में उ0प्र0 के औद्योगिक विकास के स्वरूप को स्पष्ट किया गया है। वास्तव में औद्योगिक विकास से तात्पर्य उद्योगों के ऐसे नियमित एवं क्रमिक विकास से है जिससे उद्योगों में धीरे धीरे नवीनता एवं आधुनिकता का समावेश होता रहता है। इस लेख में विभिन्न योजनाकालों में उ0प्र0 की वार्षिक वृद्धि को दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त भिन्न भिन्न उद्योगों जैसे खाद्य प्रसंस्करण व कृषि आधारित उद्योग, लघु एवं कुटीर उद्योग, वृहत एवं मध्यम उद्योगों का प्रगतिवार विवरण दिया गया है। किसी भी राष्ट्र की औद्योगिक प्रगति एक सफल सुनिश्चित सुनियोजित व प्रेरणादायक नीति पर भी आधारित होती है। उ0प्र0 प्रदेश की कोई पृथक से औद्योगिक नीतियां नहीं रही हैं जो नीतियां केन्द्र सरकार द्वारा बनायी जाती हैं उन्हीं को प्रदेश सरकार द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। प्रदेश में औद्योगिक प्रगति को तेज करने के लिए जहां एक ओर प्रभावी रणनीति तैयार की गयी है। वहीं दूसरी ओर उस रणनीति के अनुपालन हेतु सम्बन्धित संस्थाओं की स्थापना भी की गयी है। जिनमें प्रमुख रूप से उ0प्र0 वित्तिय निगम, उ0प्र0 लघु उद्योग निगम लि0, उ0प्र0 राज्य हथकरघा निगम लि0 कानपुर, उ0प्र0 राज्य वस्त्र निगम लि0 कानपुर, उ0प्र0 निर्यात निगम लि0 लखनऊ आदि प्रमुख हैं जिनका प्रदेश के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

मुख्य शब्द : औद्योगिक प्रगति, लघु उद्योग, स्वरोजगार।

प्रस्तावना

वर्तमान युग एक प्रगतिशील एवं विकासोन्मुख युग है। वर्तमान युग में अखिल विश्व में प्रत्येक राष्ट्र प्रायः इस बात के लिए निरन्तर प्रयत्नशील रहता है कि वह अपने पास उपलब्ध समस्त संसाधनों एवं सम्पदाओं का अधिक से अधिक विदोहन करके अपने राष्ट्र को औद्योगिक विकास के चरम सीमा तक पहुंचा सकें। औद्योगिक विकास ही आज किसी राष्ट्र के समुचित विकास का प्रमुख आधार स्तम्भ है। वर्तमान युग में औद्योगिक विकास किसी भी राष्ट्र के सर्वांगीण विकास का पर्यायवाची माना जाने लगा है। अतः किसी भी राष्ट्र के आर्थिक विकास के लिए यह बाद परमावश्यक है कि उस राष्ट्र में नवीन उद्योंगों की स्थापना एवं उसके विकास पर विशेष बल दिया जाये तथा इसके साथ पहले से कार्यरत औद्योगिक संस्थाओं को भी पर्याप्त मात्रा में विकास के सुअवसर प्रदान किये जायें।

वास्तव में औद्योगिक विकास से तात्पर्य उद्योगों के ऐसे नियमित एवं क्रमिक विकास से है जिससे उद्योगों में धीरे–धीरे नवीनता एवं आधुनिकता का समावेश होता रहता है। मशीनों का उपयोग क्रमिक रूप से बढ़ने लगता है तथा उद्योंगों द्वारा निर्मित वस्तुओं में समयनुसार एवं आवश्यकतानुसार परिवर्तन होते रहते हैं। इसके अतिरिक्त औद्योगिक विकास के अन्तर्गत किसी भी राष्ट्र के उन विभिन्न क्षेत्रों का भी पता लगाया जाता है जिन क्षेत्रों में नवीन उद्योगों की स्थापना हेतु सम्भावनायें प्रबल होती हैं। इसके साथ ही साथ इन विभिन्न नवीन क्षेत्रों में उचित एवं अनुकूल नये उद्योगों की स्थापना की भी समुचित व्यवस्था की जाती है ताकि औद्योगिक विकास की बढ़ती हुई गति को एक ओर नवीन तीव्रता प्रदान की जा सके।

अध्ययन का उद्देश्य

अध्ययन का उद्देश्य उ0प्र0 की औद्योगिक प्रगति का विवेचनात्मक अध्ययन करना है। प्रदेश के संतुलित आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने की दृष्टि से सरकार द्वारा प्रदेश में सुनियोजित योजनायें बनायी गयी हैं। जिनका

मुख्य उद्देश्य प्रदेश में वर्तमान कार्यरत उद्योगों को सुचारू रूप से कार्य करते रहने के साथ–साथ औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हेतु प्रयास करना है। प्रदेश की औद्योगिक नीति को इस प्रकार बनाया गया है कि उत्तर प्रदेश के उद्यमियों के साथ–साथ प्रवासीय भारतीय उद्यमियों को उद्योग स्थापना हेतु प्रोत्साहित किया जा सके। प्रदेश के सभी क्षेत्रों में विकास सुनिश्चित करने के लिए औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में कुछ विशिष्ट सहायतायें उपलब्ध कराई जा रही हैं। यह प्रयास कराया जा रहा है कि प्रत्येक जिले में एक औद्योगिक ढांचा तैयार किया जाय जिससे विभिन्न औद्योगिक योजनायें अल्प अवधि में क्रियान्वित की जा सकें।

अध्ययन की अवधि

हमारे अध्ययन की अवधि वर्ष 2005 से वर्ष 2008 के मध्य के वर्ष की है। अतः उक्त अवधि तक योजनाओं का प्रदेश के औद्योगिक विकास जो योगदान रहा है उसका विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है।

विभिन्न योजनाकालों में उ0प्र0 राज्य की वार्षिक आर्थिक वृद्धि दर

क्र0 सं0	योजना	योजना अवधि	वृद्धि दर (%) में
1.	पहली पंचवर्षीय योजना	1951 – 1956	2.3
2.	दूसरी पंचवर्षीय योजना	1956 – 1961	1.7
3.	तीसरी पंचवर्षीय योजना	1961 – 1966	5.7
4.	तीन पंचवर्षीय योजना	1966 – 1969	1.2
5.	चौथी पंचवर्षीय योजना	1969 – 1974	3.4
6.	पांचवीं पंचवर्षीय योजना	1974 – 1979	9.4
7.	छठवीं पंचवर्षीय योजना	1980 – 1985	4.8
8.	सातवीं पंचवर्षीय योजना	1985 – 1990	10.9
9.	आठवीं पंचवर्षीय योजना	1992 – 1997	4.2
10	नवीं पंचवर्षीय योजना	1997 – 2002	3.0
11.	दसवीं पंचवर्षीय योजना	2002 – 2007 (दिसम्बर 2005 तक)	7.3

स्त्रोत : उ0प्र0 में औद्योगिक विकास प्रगति समीक्षा 2005–06

प्रदेश के आर्थिक विकास में उद्योगों का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रदेश के औद्योगिकरण एवं रोजगार सृजन में लघु उद्योग, हस्तशिल्प एवं कृषि आधारित इकाइयों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि राज्य की वार्षिक वृद्धि दर पांचवीं व सातवीं योजनाकाल के अपवाद को छोडते हुए अन्य योजनाकाल में सामान्य रूप से लच्छित दर से कम रही है। नवीं योजनाकाल में राज्य की वार्षिक वृद्धि दर अनुमानित 7 प्रतिशत के विरूद्ध 3 प्रतिशत रही है।

प्रदेश में उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा 32636.96 एकड़ भूमि में कुल 95 औद्योगिक क्षेत्र विकसित किये गये हैं इसके साथ ही साथ उद्योग निदेशालय द्वारा 80 वृहद एवं 168 मिनी औद्योगिक अस्थानों की स्थापना भी करायी गयी है। उपरोक्त के अतिरिक्त यू0पी0एस0आई0डी0सी0 द्वारा उत्पाद विशेष हेतु इन्डस्ट्रियल पार्क भी विकसित किये गये हैं जिनमें निम्नलिखित मुख्य रूप से उल्लेखनीय हैं –

1. एपारेल पार्क, ट्रोनिक सिटी, गाजियाबाद।
2. टेक्साटाइल एवं होजरी पार्क, कानपुर।
3. लेदर टेक्नोलाजी पार्क, बन्थर, उन्नाव।
4. साफ्टवेयर टेक्नोलाजी पार्क, कानपुर।
5. एग्रो काम्पलेक्स वाराणसी, लखनऊ।
6. निर्यात संवर्द्धन, औद्योगिक पार्क, ग्रेटर नोएडा/आगरा।

उक्त के साथ ही साथ ग्रेटर नोएडा, कानपुर, भदोही, एवं मुरादाबाद में विशेष आर्थिक परिक्षेत्रों की भी स्थापना उद्यमियों को अवस्थापना सुविधा उपलब्ध कराये जाने की दृष्टिकोण से की जा रही है। इसके अतिरिक्त हस्तशिल्प एक्सपोर्ट प्रमोशन काउन्सिल द्वारा भी एक एक अतिरिक्त विशेष आर्थिक परिक्षेत्र की स्थापना नोएडा में प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश पहला राज्य है, जिसके द्वारा ''उत्तर प्रदेश विशेष आर्थिक परिक्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम – 2002'' पारित किया गया है।

खाद्य प्रसंस्करण एवं कृषि आधारित उद्योग

उत्तर प्रदेश राज्य देश के 1/6 भाग की आबादी से बसा हुआ है तथा भौगोलिक दृष्टि से चौथे नम्बर पर है। इस राज्य में प्रमुखतः कृषि एवं उद्यान से राज्य की मुख्य अर्थव्यवस्था विकसित है। उत्तर प्रदेश में देश के सापेक्ष प्रमुखतः 19 प्रतिशत फूड ग्रेन उत्पादन होता है। इनमें प्रमुखतया गेहूं, तिलहन, आलू, गन्ना, धान तथा विभिन्न प्रकार के फल हैं। इसके अतिरिक्त देश के सापेक्ष लगभग 78 प्रतिशत पशुओं की संख्या जिनमें 17.90 प्रतिशत दुग्ध का उत्पादन होता है, का देश में प्रथम उत्पादक राज्य है। नई औद्योगिक नीति में फूड प्रोसेसिंग उद्योग पर बल दिया गया है। कृषि उत्पादनों पर आधारित उद्योगों को विकसित करना राज्य सरकार की नीति का मुख्य अंग है। इन उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु हापुड़, सहारनपुर, वाराणसी व लखनऊ के पास फल एवं सब्जी, प्रसंस्करण हेतु एग्रो काम्प्लेक्स व फूड पार्क की स्थापना पर कार्य किया जा रहा है। प्रदेश में कृषि का लगभग 43 प्रतिशत योगदान है जबकि उद्योग एवं अन्य सेवाओं का क्रमशः 20 एवं 37 प्रतिशत है।

उत्तर प्रदेश में दिसम्बर 2005 तक खाद्य प्रसंस्करण एवं कृषि आधारित उद्योगों की सेक्टरवार प्रगति का विवरण अधोलिखित तालिका द्वारा दर्शाया गया है।

खाद्य प्रसंस्करण एवं कृषि आधारित उद्योगों की श्रेणीवार प्रगति का विवरण
(दिसम्बर 2005 तक)

क्र0 सं0	उत्पाद का नाम	उत्पादन देश में (मिलियन टन में)	उत्पादन उ0प्र0 में (मिलियन टन में)	प्रदेश का प्रतिशत उत्पादन में
1.	फूड ग्रेन	1980	41	22
2.	गेहूं	66	28	35
3.	गन्ना	234	108	46
4.	मक्का	9.57	1.39	14.4
5.	सब्जियां	72	17	20
6.	जानवर (दुधारू पशु)	396	70	16.6
7.	दूध	71	14.34	18
8.	धान	80	12.90	15
9.	तिलहन	15	1	9
10.	फल	42	8.8	18

स्त्रोतः उ0 प्र0 में औद्योगिक विकास प्रगति समीक्षा 2005 – 06

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि खाद्य प्रसंस्करण व कृषि आधारित उद्योगों में सर्वाधिक प्रतिशत देश में गन्ना (46 प्रतिशत) व गेहूं (35 प्रतिशत) का है। यदि इन उद्योगों के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाए तो औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।

हस्तशिल्प एवं निर्यात प्रोत्साहन

प्रदेश के औद्योगिक विकास में हस्तशिल्प का विशेष योगदान है। प्रदेश में लगभग 10 लाख हस्तशिल्पी एवं 1.00 लाख हस्तशिल्प इकाइयां है। आगरा का मार्बल उद्योग, सहारनपुर का वूडकार्विंग, लखनऊ का चिकन उद्योग, कानपुर एवं आगरा के चर्म उत्पाद, मुरादाबाद का पीतल उद्योग, फिरोजाबाद का ग्लास उद्योग, खुर्जा का सिरामिक एवं पाटरी उद्योग एवं भदोही का कारपेट उद्योग विश्व पटल पर प्रख्यात हैं।

शिल्पियों को स्वयं सहायता समूहों में आर्थिक रूप से संगत बनाने के लिए अम्बेदकर हस्तशिल्प विकास योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा प्रदेश में 36 एन0जी0ओ0 चयनित किये गये हैं, जिनके माध्यम से 594 स्वयं सहायता समूह गठित किये जा चुके हैं। शिल्पियों को आर्थिक सहायता सुगमता से उपलब्ध कराने हेतु बैंकों के माध्यम से क्रेडिट कार्ड योजना विगत वर्ष से संचालित की गयी है, जिसके अन्तर्गत गत वर्ष एवं दिसम्बर 2005 तक चालू वित्तीय वर्ष में कुल 5268 शिल्पियों को क्रेडिट कार्ड की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है तथा 6345 शिल्पियों को पहचान पत्र जारी किये गये हैं।

लघु एवं कुटरी उद्योग

लघु उद्योग वे उद्योग हैं जिसमें नियत परिसम्पत्तियों (संयंत्र और मशीनरी) में निवेश एक करोड़ रूपये से अधिक न हो। प्रौद्योगिकी उन्नयन में सहायता पहुंचाने के लिए 71 उच्च प्रौद्योगिकी/निर्यातोन्मुखी उद्योगों की सीमा बढ़ाकर 5 करोड़ रूपये तक की गयी है।

लघु उद्योग क्षेत्र देश की आर्थिक संरचना का एक महत्वपूर्ण आवश्यक घटक है। यह क्षेत्र राष्ट्र की आर्थिक प्रगति और विकास का बीजमंत्र है जो कि इसके औद्योगिक उत्पादन रोजगार सृजन और निर्यात में योगदान से विदित है। लघु उद्योगों में संरचनात्मक परिवर्तन भी हो रहा है, जैसे कि सूचना प्रौद्योगिकी। जैव प्रौद्योगिकी खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्र इत्यादि। इन सबके द्वारा लघु उद्योगों का विकास अब नये आयाम प्राप्त कर रहा है। प्रदेश के औद्योगीकरण एवं रोजगार सृजन में लघु, हस्तशिल्प एवं कृषि आधारित इकाइयों की महत्वपूर्ण भूमिका है। खाद्य एवं कृषि उत्पाद, चर्म उत्पाद, होजरी एवं गारमेन्ट्स, मेटल आर्टवेयर, इन्जीनियरिंग आइटम, रिपेयरिंग एवं सर्विस उद्योग आदि प्रदेश के लघु उद्योग क्षेत्र के प्रमुख उद्योग हैं।

उत्तर प्रदेश में माह दिसम्बर 2005 तक कुल 5,21,835 लघु औद्योगिक इकाइयां स्थापित हुई हैं जिसमें लगभग 5130.82 करोड़ रूपये का पूँजी विनियोजन तथा 2000649 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध हुआ है। दिसम्बर 2005 तक स्थापित लघु एवं लघुत्तर उद्योगों की श्रेणीवार प्रगति का विवरण अधोलिखित है –

क्र0 सं0	उद्योग श्रेणी	लघु उद्योगों की संख्या	प्रतिशत	पूँजी निवेश (करोड़ में)	पूँजी प्रतिशत	सृजित रोजगार संख्या	रोजगार प्रतिशत
1.	खाद्य उत्पाद	77883	13.00	956.83	13.00	278904	13.00
2.	पेय तम्बाकू एवं तम्बाकू उत्पाद	1792	0.2	28.52	0.50	9770	0.50
3.	काटन टेक्सटाइल	11701	2.00	123.02	2.00	51699	2.00
4.	ऊन, सिल्क, एवं सिन्थेटिक फाइबर टेक्स0	10673	2.00	87.35	1.00	41982	2.00
5.	जूट, हेम्प एवं मस्ता टेक्सटाइल	2585	3.00	19.09	0.40	10203	0.50
6.	होजरी एवं गारमेन्ट्स	55610	6.00	22.36	4.00	117684	5.00
7.	वुड प्रोडक्ट्स	33919	6.00	22.36	4.00	117684	5.00
8.	पेपर प्रोडक्ट्स एवं प्रिन्टिंग	11251	2.00	191.04	3.00	89642	4.00
9.	लेदर प्रोडक्ट्स						
10.	रबर एवं प्लास्टिक प्रोडक्ट्स	9451	1.00	290.63	5.00	50538	2.00
11.	केमिकल एवं केमिकल प्रोडक्ट्स	11730	2.00	170.88	3.00	95218	4.00

12.	नान–मैटेलिक मिनरल प्रोडक्ट्स	10524	2.00	170.68	3.00	95218	4.00
13.	बेसिक मेटल इण्डस्ट्रीज	6090	1.00	161.68	3.00	33801	1.00
14.	मेटल प्रोडक्ट्स	31369	6.00	402.34	7.00	142040	7.00
15.	मशीनरी एण्ड पार्टस् सक्सप्ट इलेक्ट्रिकल	12630	2.00	262.72	5.00	58970	2.00
16.	इलेक्ट्रिकल मशीनरी एण्ड आपरेट्स	8703	1.00	157.31	3.00	40774	2.00
17.	ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट्स एण्ड पार्ट्स	3336	0.6	121.37	2.00	21158	1.00
18.	मिसलेनियस मैन्यूफैक्चरिंग	71671	13.00	500.75	9.00	247761	12.00
19.	रिपेयरिंग एण्ड सर्विसिंग इण्डस्ट्रीज	135824	26.00	585.46	11.00	387565	19.00
		521835		5130.82		2000649	

स्रोत : उ0प्र0 में औद्योगिक विकास प्रगति समीक्षा – 2005

उपर्युक्त तालिका दिसम्बर 2005 तक स्थापित लघु एवं लघुत्तर उद्योगों की श्रेणीवार प्रगति पूँजी विनियोजन व रोजगार से सम्बन्धित आंकड़े दर्शाए गये हैं। सबसे अधिक इकाइयां 135824 रिपेयरिंग एण्ड सर्विसिंग इंडस्ट्रीज से सम्बन्धित है। जो कुल इकाइयों का 13 प्रतिशत है और सबसे कम इकाइयां पेय तम्बाकू एवं तम्बाकू उत्पादन 1792 हैं जो कुल इकाइयों का 2 प्रतिशत हैं। दूसरा स्थान खाद्य उत्पाद से सम्बन्धित वस्तुओं का है जो कुल का 13 प्रतिशत है और रोजगार भी 18 प्रतिशत है।

वृहद उद्योग एवं मध्यम उद्योग क्षेत्र

भारी एवं मध्यम उद्योगों के क्षेत्र में प्रदेश उत्तरोत्तर प्रगति पर है। सातवीं योजना के अन्त तक इस श्रेणी की 939 इकाइयों की स्थापना हो चुकी थी जिसमें कुल पूँजी विनियोजन 7843 करोड़ तथा रोजगार सृजन 448938 व्यक्तियों का था। नवीं योजना के अन्त तक कुल 3500 वृहत एवं मध्यम स्तरीय उद्योग स्थापित हो चुके हैं जिनमें पूँजी विनियोजन रू0 25629.32 करोड़ एवं 946982 व्यक्तियों को रोजगार के अवसर सुलभ हुए हैं।

स्टार कैटेगरी योजना

देश में प्रथम बार अच्छे उद्योगों को प्रतिष्ठा दिलाने एवं उनको प्रोत्साहित करने हेतु विभिन्न श्रेणियों में स्टार से अलंकृत करने की योजना उत्तर प्रदेश में प्रारम्भ की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश को अच्छी औद्योगिक इकाइयों को उनकी अच्छी उपलब्धियों के आधार पर एक से सात श्रेणियों से अलंकृत किया जाता है।

स्टार कैटेगरी प्रदान किये जाने हेतु शासन द्वारा राज्य स्तरीय समिति गठित की गयी है जिसके द्वारा अब तक 949 उद्योगों को शासनादेश के अनुसार विभिन्न श्रेणियों से अलंकृत किया जा चुका है। उपरोक्त सुविधाओं के अतिरिक्त इस योजना को और अधिक आकर्षक एवं प्रभावी बनाने हेतु निदेशालय द्वारा शासन स्तर पर प्रयास किये जा रहे हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार की औद्योगिक नीतियां

उत्तर प्रदेश सरकार की कोई पृथक से औद्योगिक नीतियां नहीं हैं, जो नीतियां केन्द्र सरकार द्वारा बनायी जाती हैं, उन्हीं को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। प्रदेश में लम्बे समय से कोई स्थिर सरकार न होने के कारण प्रदेश की औद्योगिक प्रगति पर ठीक से ध्यान नहीं दिया गया है। प्रदेश में कोई भी सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पा रही है, कभी समाजवादी पार्टी का शासन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का शासन फिर इसके बाद राज्यपाल का शासन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का शासन और फिर से राज्यपाल शासन तदुपरान्त भारतीय जनता पार्टी बहुजन समाज पार्टी की साझा सरकार का शासन हो गया। इन सब कारणो से कोई भी सरकार औद्योगिक नीतियों को क्रियान्वित करने पर ठीक से ध्यान नहीं दे पायी है।

विकास से सम्बन्धित संस्थायें

प्रदेश में औद्योगिक प्रगति की गति को तेज करने के लिए जहां एक ओर प्रभावी रणनीति तैयार की गयी है वहीं दूसरी ओर उस रणनीति के अनुपालन हेतु सम्बन्धित संस्थाओं की स्थापना की गयी है। यह संस्थायें किस प्रकार अपना योगदान प्रदान कर रही हैं, इसका विवरण निम्नांकित है –

उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कानपुर

उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम (यू0 पी0 एफ0 सी0) की स्थापना 1 नवम्बर 1954 को राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत की गयी थी। यू0 पी0 एफ0 सी0 ने लघु एवं मध्यम वर्गीय उद्योगों के माध्यम से प्रदेश के सर्वांगीण विकास को सुदृढ़ बनाने का विनम्र प्रयास किया है।

यू0 पी0 एफ0 सी0 ने 31 मार्च 2005 तक 41168 मामलों में रू0 3189.73 करोड़ की दीर्घावधि ऋण के रूप में वित्त पोषित की है।

उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड

उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना प्रदेश लघु उद्योग इकाइयों के वृहत विकास सम्बनधी आवश्यक पोषण एवं प्रगति हेतु एक पूर्ण स्वामित्वाधीन कम्पनी के रूप में जून 1958 में की गयी थी। शासन के निर्देशों के क्रम में समय–समय पर औद्योगिक विकास विषयक योजनाओं का कार्यान्वयन किया गया। निगम द्वारा पूर्व में लघु औद्योगिक इकाइयों के विकास हेतु कच्चे माल की उपलब्धता, किराया क्रय आधार पर मशीनों की आपूर्ति, संकुल समूहों के विकास हेतु कच्चे माल की उपलब्धता, किराया क्रय आधार पर मशीनों की आपूर्ति,

बुनकरों, ऊनी धागा एवं रंगों की आपूर्ति उद्योग निदेशालय द्वारा स्थानान्तरित बीमार इकाइयों का संचालन एवं संयुक्त क्षेत्र में अंश पूंजी भागीदारी की भूमिका निभाई गयी।

निगम की अधिकृत पूँजी रू0 25.00 करोड़ है। शासन ने निगम को अब तक मात्र रू0 596.05 लाख की पूँजी प्रदान की है। प्रीइम्लीमेंटेशन सपोर्ट एक्टिविटीज में विनियोजन की राशि की वसूली न होने के कारण कार्यशील पूँजी के अभाव में निगम वित्तीय संस्थाओं के सहयोग से कार्य कर रहा है। जिससे आय का अधिकांश भाग ब्याज के रूप में चला जाता है। अपने व्यवसायिक कार्यकलापों हेतु निगम ने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक से 5.00 करोड़ रूपये का ऋण तथा 1.30 करोड़ रू0 काल इन आफ क्रेडिट स्वीकृति कराई है। इसके अतिरिक्त बैंक आफ इण्डिया से 8.00 करोड़ रू0 कैश क्रेडिट सीमा स्वीकृति करा रखी है।

उ0प्र0 राज्य हथकरघा निगम लि0 कानपुर

उ0प्र0 सरकार द्वारा प्रदेश के लाखों बुनकरों की समस्या का अध्ययन करने के लिए गठित राम सहाय आयोग की संस्तुतियों के आधार पर 9 जनवरी 1973 को कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 617 के अन्तर्गत उ0प्र0 राज्य हथकरघा निगम लिमिटेड में परिवर्तित हुआ। वर्ष 1996–97 में हुए सर्वेक्षण के अनुसार उ0प्र0 में कुल बुनकरों की संख्या 6.64 लाख तथा करघों की संख्या 2.24 लाख है। उत्पादन केन्द्रों की संख्या 16 व बिक्री केन्द्रों की संख्या 97 है। 10 क्षेत्रीय विपणन कार्यालय है।

उ0प्र0 राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड, कानपुर

उ0प्र0 राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड की स्थापना 2 दिसम्बर 1969 को उ0प्र0 सरकार की एक कम्पनी के रूप में हुई थी इसका मुख्य कार्यकलाप सूत का उत्पादन करके विकेन्द्रित क्षेत्र में बुनकरों को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराना था। निरन्तर होने वाले घाटे एवं कार्यशील पूंजी की कमी के कारण निगम की सभी कताई मिलों में उत्पादन प्रक्रिया प्रश्नगत वर्षों में शून्य थी।

उ0प्र0 निर्यात निगम लि0 लखनऊ

उ0प्र0 निर्यात निगम लि0 की स्थापना दिनांक 20 जनवरी 1966 को कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत एक लिमिटेड कम्पनी के रूप में की गई थी। स्थापना के समय निगम का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में उपलब्ध विभिन्न वस्तुओं के निर्यात को प्रोत्साहित करना था। निगम की अधिकृत पूंजी 800 लाख है तथा प्रदत्ते पूंजी 674 लाख है। वर्तमान में निगम का मुख्य उद्देश्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा वस्त्रों का विकास एवं विपणन करना है। निगम की गतिविधियों के मुख्यतः चार पहलू हैं –

1. आन्तरिक विपणन
2. हस्तशिल्प विकास
3. निर्यात प्रोत्साहन
4. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार।

निष्कर्ष

उपरोक्त अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि हमारे प्रदेश की सरकार ने विभिन्न औद्योगिक नीतियों का अनुपालन करते हुए निगमों की स्थापना की है। जो प्रदेश के औद्योगिक विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। किसी उद्यमी ने यदि यह निर्णय ले लिया कि उसे उद्योग की स्थापना करनी है तो प्रदेश में कार्यरत विभिन्न निगम उद्यमी को समुचित सेवा उपलब्ध कराने के लिए तत्पर है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

सांख्यिकी पत्रिका (2005 – 06)
उ0 प्र0 में औद्योगिक विकास प्रगति समीक्षा (2005 – 06)
औद्योगिक विवरिणका।
इकोनांमिक सर्वे ऑफ इण्डिया 2005
कुरूक्षेत्र
वार्षिक प्रतिवेदन 2005–06 कानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास (प्रगति समीक्षा) 2005 – 06 उद्योग निदेशालय उ0प्र0 कानपुर।